आनंद शरदचंद्र ओक

बनाम

मुंबई विश्वविद्यालय और अन्य

(सिविल अपील सं. 967/2008)

04 फरवरी,2008

(सी. के. ठाकर और अल्टमास कबीर, जे. जे.)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994:

धारा.2(36) और 99(1)(ए) आरएलडब्ल्यू धारा 25- मुंबई विश्वविद्यालय 7 सीनेट के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची - मतदाता सूची में 'विश्वविद्यालय के स्नातकों' का पंजीकरण - एक स्नातक द्वारा रिट याचिका मुंबई विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर का भी तर्क है कि अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को भी मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए: उप-धारा के खंड (ए) (1) धारा 99 स्पष्ट और स्पष्ट है - यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि केवल वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, वे पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के हकदार हैं - 'विश्वविद्यालय के स्नातक' शब्द की व्याख्या 'विश्वविद्यालय

द्वारा दिया गया आदेश अनुचित, अवैध या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है - रिट याचिकाकर्ता मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक है और मतदाता सूची में पंजीकृत होने के योग्य है, वह 'पीड़ित पक्ष' नहीं था - भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - रिट याचिकाकर्ता 'पीड़ित पक्ष' नहीं है - याचिका पीआईएल के तहत दायर नहीं की गई है - अभ्यास और प्रक्रिया की पोषणीयता।

क़ानून की व्याख्या:

वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या - आयोजित: • संवैधानिक वैधता के लिए किसी भी चुनौती की अनुपस्थिति में, क़ानून की किताब में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों और परिभाषित शब्दों की शाब्दिक व्याख्या दी जानी चाहिए।

अपीलकर्ता, जो प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर भी है, ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें विश्वविद्यालय की उस अधिसूचना पर सवाल उठाया गया जिसमें उन लोगों से आवेदन मांगे गए थे जिन्होंने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी ताकि वे अपना नाम चुनाव में पंजीकृत करा सकें। विश्वविद्यालय के सीनेट में सदस्यों के चुनाव के लिए रोल। अपीलकर्ता ने विश्वविद्यालय द्वारा 'विश्वविद्यालय के स्नातक' शब्द की व्याख्या को चुनौती दी और तर्क दिया कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री वाले व्यक्ति को केवल इस आधार पर पंजीकरण से वंचित नहीं किया

जा सकता है कि उसने उक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की है।

प्रत्यर्थीओं ने रिट याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता को 'पीड़ित पक्ष' नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक था और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता था, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने पर कोई शिकायत नहीं है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रिट याचिकाकर्ता 'पीड़ित पक्ष' नहीं था।

रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर तत्काल अपील में, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने लोकस स्टैंडी के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या से जुड़े कानून के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए आयोजित किया

1. यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने रिट-याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की थी। उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिट-याचिकाकर्ता ने बी.ए. प्राप्त किया है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री. इस

प्रकार, रिट-याचिकाकर्ता प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक था। इसलिए, उनका नाम सीनेट के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है। इसलिए, वह 'पीड़ित पक्ष' नहीं था। रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में नहीं थी और यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए था। इसलिए, उस सीमा तक, रिट-याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई शिकायत उचित नहीं है। [पैरा 11] [303-जी; 304-ए]

2.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 99(1)(ए) में वर्णित 'विश्वविद्यालय के स्नातक' शब्द की प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की व्याख्या अनुचित, अवैध या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। [पैरा 15] [305-ई]

2.2 अधिनियम की धारा 99 एक भौतिक प्रावधान है और पंजीकृत स्नातकों के लिए प्रावधान करती है, जो विश्वविद्यालय की सीनेट में सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदाता सूची में शामिल होते हैं। अधिनियम की धारा 25 के मद्देनजर विश्वविद्यालय की "सीनेट" सभी वित्तीय अनुमानों और बजटीय विनियोगों के लिए और वर्तमान और भविष्य पर विश्वविद्यालय को सामाजिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रमुख प्राधिकारी है। शैक्षणिक कार्यक्रम और इसके संविधान का भी प्रावधान करता है। [पैरा 4 और 13] [301-बी; 304-एफ, जी]

2.3 धारा 99 की उपधारा (1) का खंड (ए) अधिनियम स्पष्ट एवं सुस्पष्ट है। यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि केवल वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, वे पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह भी नहीं था कि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (36) के आलोक में धारा 99 पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय गलत था या उसने प्रावधान की व्याख्या करने में कोई त्रुटि की और किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार, ऐसी व्याख्या के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जा सकती। [पैरा 15 और 18] [305-सी, 0, ई; 306-ई, एफ]

2.4 यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यदि बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने स्नातक की डिग्री किसी अन्य विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, लेकिन मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों के रूप में शामिल होने के लिए पात्र और योग्य माना जाता है। 1994 के अधिनियम को लागू करते समय विधायिका जानबूझकर और जानबूझकर इससे हट गई और पंजीकरण को उन लोगों तक सीमित कर

दिया, जिन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया होगा। [पैरा 16] [305-जी, एच; 306-ए, बी.जे]

2.5 स्नातकों के पंजीकरण की व्यवस्था करना विधायिका का काम है और संवैधानिक वैधता को किसी भी चुनौती के अभाव में, क़ानून की किताब में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों और परिभाषित शब्दों की शाब्दिक व्याख्या करनी होगी। [पैरा 17] [306-डी, ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 967/2008

बॉम्बे उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन सं. 1513/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 8.8.2005 से

अपीलार्थी की ओर से विनय नवारे और नरेश कुमार।

प्रत्यर्थीओं की ओर से रवींद्र केशवराव अदसुरे और एस. एस. शिंदे।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति श्री सी.के. ठक्कर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील 2005 की रिट याचिका संख्या 1513 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 8 अगस्त 2005 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि रिट याचिकाकर्ता को 'पीड़ित

पक्ष' नहीं कहा जा सकता। उक्त निष्कर्ष के मद्देनजर हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए सवाल पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में बताए गए हैं कि पहला प्रतिवादी मुंबई विश्वविद्यालय है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 के कुलपति और रजिस्ट्रार हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 महाराष्ट्र राज्य हैं। विश्वविद्यालय महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

4. 2 अगस्त, 1999 को, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालय के सीनेट में दस सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत स्नातकों से आवेदन मांगे। रिट-याचिकाकर्ता जिसके पास एलएलएम है। विश्वविद्यालय की डिग्री ने उक्त रोल में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने रिट याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपना बैचलर डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा गया कि क्या उसने उक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की है। उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें केवल इस आधार पर पंजीकरण से वंचित नहीं किया जा

सकता कि उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं की है। इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता ने 'स्नातक' शब्द पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा की गई व्याख्या को चुनौती देते हुए 2000 की रिट याचिका संख्या 436 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया तथ्य पाया और नियम निसी जारी करके याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके थे और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा और यह देखते हुए इसका निपटारा कर दिया कि याचिका बन गई है। 'निष्फल'. हालाँकि, कानून का प्रश्न खुला रखा गया था। इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता ने 'स्नातक' शब्द पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा की गई व्याख्या को चुनौती देते हुए 2000 की रिट याचिका संख्या 436 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया तथ्य पाया और नियम निसी जारी करके याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके थे और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा और यह देखते हुए इसका निपटारा कर दिया कि याचिका बन गई है। 'निष्फल'. हालाँकि, कानून का प्रश्न खुला रखा गया

था। इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता ने 'स्नातक' शब्द पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा की गई व्याख्या को चुनौती देते हुए 2000 की रिट याचिका संख्या 436 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया तथ्य पाया और नियम निसी जारी करके याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके थे और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा और यह देखते हुए इसका निपटारा कर दिया कि याचिका बन गई है। 'निष्फल'. हालाँकि, कानून का प्रश्न खुला रखा गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया तथ्य पाया और नियम निसी जारी करके याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके थे और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा और यह देखते हुए इसका निपटारा कर दिया कि याचिका बन गई है। 'निष्फल'. हालाँकि, कानून का प्रश्न खुला रखा गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के तर्क में प्रथम दृष्टया तथ्य पाया और नियम निसी जारी करके याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई के लिए आई, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके थे और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न पर कोई

राय व्यक्त करना उचित नहीं समझा और यह देखते हुए इसका निपटारा कर दिया कि याचिका बन गई है। 'निष्फल'. हालाँकि, कानून का प्रश्न खुला रखा गया था।

5. एक बार फिर जब चुनाव होने वाले थे तो 'ग्रेजुएट' शब्द की व्याख्या का प्रश्न विचार के लिए आया। रिट-याचिकाकर्ता ने कानूनी मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए 25 अक्टूबर 2004 को विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा। हालाँकि, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया और सीनेट के चुनाव के लिए 22 अप्रैल, 2005 को एक अधिसूचना जारी की। इसमें उन लोगों के नाम दर्ज करने पर जोर दिया गया, जिन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका, यानी 2005 की रिट याचिका 1513 दायर करके फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया और प्रत्यर्थी उपस्थित हुए। प्रत्यर्थीओं की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह तर्क दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता को इस तथ्य के मद्देनजर 'पीड़ित पक्ष' नहीं कहा जा सकता है कि उसने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की थी जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की

थी और उसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने से वंचित कर दिया गया था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की थी जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी और उसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने से वंचित कर दिया गया था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की थी जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी और उसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने से वंचित कर दिया गया था। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

6. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा कि रिट-याचिकाकर्ता स्वयं एक स्नातक था जिसने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। इसलिए, उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं हो सकती। रिट याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय प्रतिबंधित तरीके से 'स्नातक' शब्द की गलत व्याख्या कर रहा था और कई अन्य व्यक्ति जो प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं थे, लेकिन विश्वविद्यालय से मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी, उन्हें इसमें नामांकित नहीं किया गया था। मतदाता सूची. उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि रिट-

याचिकाकर्ता 'पीड़ित पक्ष' नहीं था, इसलिए याचिका खारिज होने योग्य थी और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को वर्तमान अपील में रिट याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है।

7. इस न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2006 को नोटिस जारी किया गया था और 27 अगस्त 2006 को रजिस्ट्री को मामले को गैर-विविध दिन पर सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया गया था। इस तरह मामला हमारे सामने रखा गया है।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा लोकस स्टैंडी के आधार पर याचिका को खारिज करना गलत था। न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि प्रश्न कानून की व्याख्या का था और उसे इस मुद्दे को किसी न किसी तरह से तय करना चाहिए था। अपीलकर्ता के अनुसार, अतीत में भी, उच्च न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया और उसकी रिट याचिका को 'निष्फल' बताते हुए निपटा दिया। फिर सवाल उठा है और आगे भी हर चुनाव में ऐसा सवाल उठेगा. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि विवाद पर निर्णय न देकर उच्च न्यायालय गलत था।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करना उचित था

कि याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं था। रिट याचिका जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति में नहीं थी और जब रिट-याचिकाकर्ता स्वयं प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक था, तो उसका नाम मतदाता सूची में हो सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बड़े प्रश्न पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, वकील ने स्वीकार किया कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक किया होगा और बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की होगी और इस आधार पर जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किए गए होंगे। लेकिन यह प्रस्तुत किया गया कि यह कानून का प्रावधान है, यूनिवर्सिटी ने इसकी सही व्याख्या की है और उनके नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया है।' उन्होंने आगे कहा कि प्रावधान की संवैधानिक वैधता या अधिकार को रिट-याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, विश्वविद्यालय ने उन व्यक्तियों के नाम पंजीकृत नहीं करने का निर्णय लिया, जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने कहा कि अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने रिट-याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना गलत था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिट-याचिकाकर्ता ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए

की डिग्री प्राप्त की है। इस प्रकार, रिट-याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से स्नातक किया गया था। इसलिए, उनका नाम सीनेट के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में दर्ज किया जा सकता है। इसलिए, वह 'पीड़ित पक्ष' नहीं थे। रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में नहीं थी और यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय देना चाहिए था। इसलिए, उस हद तक, रिट-याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई शिकायत उचित नहीं है।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है, यह भी उतना ही सच है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक डिग्री और बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की होगी। प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या के अनुसार, उनके नाम अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए, हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या विश्वविद्यालय की कार्रवाई अवैध है, कानून के विपरीत है या अन्यथा आपत्तिजनक है। इस संबंध में प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला दिया। धारा 2 कुछ शर्तों को परिभाषित करती है और 'विश्वविद्यालय' शब्द को धारा 2 के खंड (36) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है;

"विश्वविद्यालय" का अर्थ अनुसूची में उल्लेखित विश्वविद्यालयों में से कोई भी है।

13. अधिनियम की अनुसूची विश्वविद्यालयों को निर्दिष्ट करती है। अधिनियम में 'स्नातक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 3 "विश्वविद्यालयों के निगमन" का प्रावधान करती है। धारा 6 "विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारों में प्रवेश" से संबंधित है। धारा 24 विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की गणना करती है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से एक "सीनेट" है। धारा 5 घोषित करती है कि सीनेट सभी वित्तीय अनुमानों और बजटीय विनियोगों के लिए और वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर विश्वविद्यालय को सामाजिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रधान प्राधिकारी होगी और इसके संविधान का भी प्रावधान करती है। धारा 26 सीनेट के कार्यों और कर्तव्यों का वर्णन करती है। अध्याय XI नामांकन, डिग्री और दीक्षांत समारोह से संबंधित है। धारा 99 एक भौतिक प्रावधान है और पंजीकृत स्नातकों के लिए प्रावधान करती है।

> ''(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए पंजीकृत स्नातकों या पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के हकदार होंगे, अर्थात्:

(ए) जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं;

(बी) जो वर्तमान विश्वविद्यालय से स्नातक हैं जहां से संबंधित नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है; प्रदान किया....

(2)...'' (जोर दिया गया)

14. धारा 100 कुलाधिपति को स्नातकों के रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने में सक्षम बनाती है।

15. हमारी राय में धारा 99 की उपधारा (1) का खंड (ए) स्पष्ट और स्पष्ट है। यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि केवल वे व्यक्ति जो 'विश्वविद्यालय के स्नातक' हैं, वे पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विश्वविद्यालय का अर्थ अनुसूची में उल्लिखित कोई भी विश्वविद्यालय है। यहां तक कि उच्च न्यायालय या हमारे समक्ष रिट-याचिकाकर्ता का मामला भी ऐसा नहीं है कि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की व्याख्या अनुचित, अवैध या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। हमारी राय में, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील का यह तर्क भी सही है कि वैधानिक प्रावधान की

संवैधानिक वैधता को रिट-याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और, इस प्रकार, न्यायालय को केवल प्रावधान की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है क्योंकि वह इसे मानता है। वैध हो और अधिकार के अंदर हो। यदि ऐसा है, तो न्यायालय के समक्ष सीमित विवाद यह है कि क्या विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 के साथ पढ़ी गई धारा 99 में कानून के प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या करने में सही है।

16. हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निरस्त क़ानून, अर्थात्, बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974, ऐसे व्यक्तियों को पात्र मानता है, जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में शामिल किया जाए। हालाँकि, हमारी राय में, उपरोक्त परिस्थिति, रिट-याचिकाकर्ता का समर्थन करने के बजाय प्रत्यर्थीओं का समर्थन कर सकती है क्योंकि यह कहा जा सकता है कि हालांकि पिछले अधिनियम में ऐसा प्रावधान था, विधानमंडल जानबूझकर और जानबूझकर इससे हट गया और पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया होगा। इसलिए, उक्त विवाद रिट-याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं ले जा सकता।

17. तब यह तर्क दिया गया कि कई अन्य विश्वविद्यालयों में, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन उन विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की थी, उन्हें स्नातकों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पात्र माना गया है। उस आधार पर भी, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की विवादित कार्रवाई को कानूनी या उचित नहीं कहा जा सकता है। हमें डर है, हम रिट-याचिकाकर्ता के तर्क को बरकरार नहीं रख सकते। यदि विधायिका को स्नातकों के पंजीकरण के लिए प्रावधान करना है और संवैधानिक वैधता के लिए किसी भी चुनौती के अभाव में, हमें क़ानून की किताब में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों और परिभाषित शब्दों की शाब्दिक व्याख्या करनी होगी।

18. जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है, अधिनियम की धारा 2 के खंड (36) के आलोक में धारा 99 पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय गलत था या प्रावधान की व्याख्या करने और किसी भी व्यक्ति को वंचित करने में कोई त्रुटि हुई थी। उसका अधिकार. यदि ऐसा है तो ऐसी व्याख्या के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जा सकती। इसलिए, हमें रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नजर नहीं आता।

19. उपरोक्त कारणों से, अपील/खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार, खारिज की जाती है। हालाँकि, तथ्यों और मामले की

परिस्थितियों के आधार पर, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामचरण मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।